विद्युत क्षेत्र के संबंध में मध्यावधि मूल्यांकन

1813. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने विद्युत क्षेत्र के संबंध में कोई मध्यावधि मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उसकी रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत 10,000 मेगावाट की संभावित कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है;

(घ) क्या इस कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का सुझाव दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के प्रारूप को पूरे योजना आयोग के अनुमोदन के पश्चात अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में योजना अवधि के दौरान 30,538 मेगावाट की क्षमता वृद्धि की परिकल्पना की गई है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान वास्तविक क्षमता वृद्धि 14798 मेगावाट रही है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार आठवीं योजना के दौरान प्रत्याशित क्षमता वृद्धि 18000 मेगावाट के लगभग होगी,

कमी के मुख्य कारण हैं: भूमि अधिग्रहण में देरी, कानून और व्यवस्था की समस्या, पर्यावरणीय विनियमन को कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता और निधि दबाव।

मांग और पूर्ति के बीच अंतर को कम करने के उपायों में शामिल हैं: (1) नई उत्पादन क्षमता की शुरूआत को तेज करना (2) लघु अवधि परियोजनाओं का कार्यान्वयन (3) वर्तमान पावर स्टेशनों के निष्पादन में सुधार (4) पारेषण और वितरण घाटों को कम करना (5) उत्तम मांग प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण उपाय (6) अतिरेक वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में ऊर्जा स्थानांतरण की व्यवस्था करना (7) विद्युत क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक निदेश को बढ़ावा देना।

Employment Generation and Poverty Eradiction in North East

1814. SHRI W. ANGON SINGH: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the amount of Central assistance given to the North Eastern States during 1995-96 under different employment generation and poverty eradication programmes, State-wise;

(b) the amount utilised so far during the current year; and

(c) the achievements made in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) to (c) Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS) & Integrated Rural Development Programme (IRDP) are the major employment generation and poverty eradiation programmes being implemented by the centre in different States including the North Eastern States. The amount of Central assistance given during 1995-96, the amount utilised and achievemnet made during the current year are given in the Statement in respect to North Eastern States.